स्कूल और समुदाय के बीच समन्वय जरूरी है

द्वारा: रहमदीन*

कोई भी विद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं है, बल्कि वह समाज का एक अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार किसी बच्चे के समुचित विकास के लिए केवल परिवार की भूमिका पर्याप्त नहीं होती, उसी प्रकार किसी विद्यार्थी के संपूर्ण शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए केवल विद्यालय की चारदीवारी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। जब विद्यालय और समुदाय एक-दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते हैं, तब शिक्षा का स्वरूप न केवल व्यापक होता है बल्कि अधिक सार्थक और उपयोगी भी बनता है। इस समन्वय की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है, क्योंकि शिक्षा अब केवल पुस्तकों और परीक्षा की सीमा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जीवन के अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक जुड़ाव से भी उतनी ही जुड़ी हुई है, शायद इसीलिए ही यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि एक बच्चे को पालने में पूरा गांव लगता है।

वैसे तो विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है, परंतु इस ज्ञान को जीवन से जोड़ने का कार्य समुदाय करता है। एक बच्चा विद्यालय में जो कुछ सीखता है, उसे वह समुदाय में लागू करना सीखता है। यदि स्कूल और समुदाय के बीच दूरी हो, तो ज्ञान केवल सैद्धांतिक रह जाता है, उसमें व्यवहारिक पक्ष नहीं जुड़ पाता। जब विद्यालय समुदाय के लोगों जैसेः किसान, कारीगर, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या कलाकार से जुड़ता है, तब विद्यार्थी न केवल किताबी ज्ञान, बल्कि जीवन के अनुभवों और विविध कौशलों से भी परिचित होता है। इससे शिक्षा अधिक जीवंत, रोचक और उपयोगी बनती है।

समुदाय में अनेक प्रकार के संसाधन विद्यमान होते हैं, चाहे वे भौतिक संसाधन हों, जैसे भवन, पुस्तकालय या खेल के मैदान या मानवीय संसाधन जैसेः अनुभवी नागरिक, स्थानीय नेता या विशेषज्ञ। जब विद्यालय इन संसाधनों का सहयोग लेता है, तो विद्यार्थियों को अधिक विविधतापूर्ण और समृद्ध शिक्षा मिलती है। उदाहरण के तौर पर कोई सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को निशुल्क ट्यूटरिंग दे सकता है, कोई स्थानीय चिकित्सक स्वास्थ्य शिक्षा पर सत्र ले सकता

है और कोई कलाकार बच्चों में रचनात्मकता का संचार कर सकता है। यह सब तभी संभव है जब स्कूल समुदाय से सहयोग मांगे और समुदाय अपनी भूमिका को समझते हुए आगे आए।

माता-पिता और अभिभावक भी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे अपने बच्चों की शिक्षा में सबसे नजदीकी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब वे केवल शुल्क चुकाने वाले ग्राहक की तरह विद्यालय से जुड़े रहते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। विद्यालयों को चाहिए कि वे अभिभावकों को केवल 'पैरेंट-टीचर मीटिंग' तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें विद्यालय की योजना, गतिविधियों, उत्सवों और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दें। जब अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं, तो वे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के प्रति अधिक सजग होते हैं और बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति गंभीरता विकसित होती है।

स्कूल और समुदाय के समन्वय का एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे बच्चों को सामाजिक और नैतिक शिक्षा मिलती है। एक अकेला विद्यालय जीवन के हर पहलू की शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु यदि वह समाज के अनुभवी लोगों को आमंत्रित करे, जैसेः समाजसेवियों, सेनानिवृत्त अधिकारियों, ग्रामीण बुजुर्गों, धर्मगुरुओं या सफल उद्यमियों को, तो विद्यार्थी जीवन के वास्तविक मुद्दों, संघर्षों और जिम्मेदारियों से अवगत हो सकते हैं। इससे उनके भीतर नेतृत्व, सेवा और सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न होती है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है।

इसके अतिरिक्त जब समुदाय विद्यालय के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, तो विद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ती है। समुदाय यह जान सकता है कि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कैसा है, शिक्षकों की उपस्थिति और गुणवत्ता कैसी है और किन क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता है। इससे विद्यालयों पर एक नैतिक दबाव बनता है कि वे अपने कार्यों में ईमानदारी बरतें और बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर रहें। इसी प्रकार समुदाय भी यह महसूस करता है कि विद्यालय उसके बच्चों के भविष्य की आधारशिला रख रहा है, अतः वह स्वयं भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित होता है।
आज जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, यानी कि हर वर्ग, जाति, लिंग और पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर प्रदान कराना, तब समुदाय की भागीदारी और भी ज़रूरी हो जाती है। विद्यालय यदि अपने स्थानीय समुदाय की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को समझे और उनका सम्मान करे, तो वह शिक्षा को अधिक समावेशी बना सकता है। उदाहरण के लिए किसी आदिवासी क्षेत्र के स्कूल में यदि वहां की बोली बोलने वाले शिक्षक हों, यदि पाठ्यक्रम में वहां की परंपराओं का समावेश हो और स्थानीय अभिभावकों की राय को महत्व दिया जाए, तो बच्चे शिक्षा से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करेंगे।

कोविड-19 जैसे संकटों ने तो यह और स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल और समुदाय का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं, बल्कि अत्यंत मानवीय और व्यावहारिक भी होना चाहिए। जब स्कूल बंद हुए, तब शिक्षा का पहिया ऑनलाइन माध्यमों से घुमाने के लिए स्थानीय समाज, अभिभावक, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य बन गया। यह अनुभव हमें बताता है कि किसी भी आपदा या परिवर्तन के समय शिक्षा प्रणाली केवल सरकारी आदेशों से नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता से ही टिकाऊ बन सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ना होगा, विद्यालयों को अपने समुदाय के साथ मिलकर पाठ्यक्रम, सह-पाठ्य गतिविधियाँ और शिक्षण विधियाँ विकसित करनी होंगी। इससे शिक्षा अधिक स्थानीयकृत, लचीली और उत्तरदायी बनेगी।

वास्तव में जब स्कूल और समुदाय मिलकर कार्य करते हैं, तो वे विद्यार्थियों को एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा

में तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल उनकी अकादमिक योग्यता बढ़ाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, संवेदनशील, जिम्मेदार और नवोन्मेषी बनाती है। ऐसे विद्यार्थी अपने समाज के साथ गहरे जुड़ाव रखते हैं और आगे चलकर समाज के सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनते हैं।

अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्कूल और समुदाय के बीच समन्वय कोई विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षा की सफलता के लिए अनिवार्य शर्त है। यह समन्वय शिक्षा को कक्षा से निकालकर जीवन से जोड़ता है, विद्यालय को समाज के केंद्र में स्थापित करता है और समुदाय को शिक्षा के माध्यम से अपनी भावी पीढ़ी के निर्माण में सहभागी बनाता है। हमें अब यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि विद्यालय और समुदाय जब मिलकर शिक्षा का दायित्व निभाते हैं, तभी एक समृद्ध, संवेदनशील और सशक्त समाज का निर्माण संभव हो पाता है।

*रहमदीन
प्रोग्राम कॉडिनेटर, एलएलएफ
शिक्षा सदन, पंचकूला